नीति और क्रियान्वयन में विरोधाभास

अपने दूसरे कार्यकाल में सत्ता में आने के बाद सरकार की शिक्षा के लिए पहली मुख्य घोषणा शिक्षा नीति 2019 का मसौदा सार्वजनिक करना थी। इस मसौदे का जोर इस बात पर था कि अगले 10 वर्षों में शिक्षा पर केन्द्र सरकार के खर्च को दो गुना कर दिए जाने की जरूरत है। मगर 2019 के बजट के आंकड़े इस मंशा से इत्तेफाक नहीं रखते। बजट के आंकड़े लगभग अंतरिम बजट के आंकड़ों का दोहराव भर हैं। इनमें शिक्षा के खर्च को बढ़ाने की जरूरत नहीं झलकती। इस वर्ष शिक्षा का बजट देखें तो उसके हिस्से केन्द्रीय बजट का 3.4 प्रतिशत हिस्सा आया है और जीडीपी के रूप में देखें तो यह 0.45 प्रतिशत है (अंतरिम बजट में भी इतना ही था)। अगर हम वर्ष 2014-15 के आंकड़ों को देखें तो उस वक्त यह खर्च केन्द्रीय बजट का 4.1 प्रतिशत था और जीडीपी का 0.55 प्रतिशत था। उसके बाद के वर्षों में कभी भी यह इस आंकड़े को नहीं छू पाया है बल्कि इसके नीचे ही रहा है। नई शिक्षा नीति का मसौदा ज्ञान आधारित समाज रचने का ख्वाब बुनता है इसे हकीकत में उतारने के लिए जो संसाधन चाहिए उनकी नज़र से अगर देखा जाए तो बजट उस पटरी पर आगे की दिशा लेता नहीं दिखता।

नई शिक्षा नीति का मसौदा पूर्व प्राथमिक शिक्षा व उच्च माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 12 तक) को 'मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम' (आरटीई) के दायरे में लाने की अनुशंसा करता है मगर वित्त मंत्री के बजट भाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं मिलता है। सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, व शिक्षक शिक्षा को मिला कर पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा को एक ही दायरे में लाने के लिए वर्ष 2018-19 में समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है लेकिन इसके लिए आवंटित बजट को अगर देखा जाए तो समझ आता है कि यह पुरानी अलग-अलग योजनाओं को आवंटित बजट को एक बजट में समाहित कर देना भर है।

शिक्षा नीति 2019 का मासौदा उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने व भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के एक केन्द्र के रूप में स्थापित करने के ख्वाब संजोता है। इस ख्वाब की हकीकत क्या है इसे हम नीचे दिए गए आंकड़ों की मदद से आसानी से समझ सकते हैं।

वर्ष 2018 में भारतीय शिक्षा संस्थानों में खाली पद

संस्थान का नाम	भरे पद	खाली पद
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	11486	5606
आईआईटी	5428	2802
एनआईटी	4200	3235
आईआईटी केन्द्र द्वारा वित्त पोषित	173	135
आईआईटी पीपीपी द्वारा वित्त पोषित	86	242

स्रोत : सीबीजीए द्वारा प्रस्तुत बजट विश्लेषण आंकड़े

41 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 5606 रिक्त पदों का यह आंकड़ा वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण दिए जाने तक पहुंच कर 7000 हो चुका था। अब इससे ज्यादा कुछ कहे जाने की जरूरत नहीं रह गई है।

यह अंतराल नीति सुधारों व नीति क्रियान्वय के बीच की दूरी को दर्शाता है और दर्शाता है कि नीति सुधारों को उनके लिए जरूरी संसाधन मुहैया करवाना अभी कितनी बड़ी चुनौती बना हुआ हैं। ◆